

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 568
No. 146]	DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940	[N.C.T.D. No. 568

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

सं. फा. 6/18/2018—न्याय/827—830.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 15 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या फा. यू-11030/2/2017—यूटीएल के साथ पठित वाणिज्यिक अदालतों, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा यह निर्दिष्ट करते हैं कि जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक अदालतों का आर्थिक मान तीन लाख रुपये से अधिक होगा तथा दो करोड़ रुपये तक के आर्थिक क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

अनूप कुमार मेंदीरता, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th July, 2018

No. F. 6/18/2018-Judl/827-830.—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 3 of Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 read with Notification No. U-11030/2/2017-UTL, dated the 15th May, 2018 of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, Lt. Governor, NCT of Delhi hereby specifies that pecuniary value of the Commercial Courts at the District Judge level shall be above three lakh rupees and not more than the pecuniary jurisdiction of up to two crore rupees.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ANOOP KUMAR MENDIRATTA, Pr. Secy.